E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(1): 93-94
www.journalofpoliticalscience.com
Received: xx-11-2020
Accepted: xx-12-2020

दिलबाग सिंह
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत

Corresponding Author:
दिलबाग सिंह
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत

भारत में वैश्विकरण के आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण

दिलबाग सिंह

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन वैश्विकरण द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक ढांचागत व्यवस्थाओं में उत्पन्न परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य भारतीय संदर्भ में वैश्विकरण की समझ को विकसित करना है तथा विभिन्न क्षेत्रों में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों को उल्लेखित करना है। यह अध्ययन इस बात की भी समीक्षा करता है कि वैश्विकरण की अपनी बहुतेरी चुनोतियाँ भी हैं जो इसके सतत लक्ष्यों में प्रतिरोध का कार्य कर रही हैं ।

मूल शब्द - वैश्विकरण, वैश्विक ग्राम, UNICEF, राष्ट्रीय आय

प्रस्तावना

वैश्विकरण विश्व के एकीकरण की तर्ज पर जन्मी एक विचारधारा है जिसने सम्पूर्ण विश्व के आकार को सीमित कर दिया है। वैश्विकरण एक या दो वर्षों की परिघटनाओ का परिणाम नही है बल्कि यह एक सतत एवं् विस्तृत श्रृंखला के रूप में कई वर्षों से विद्यमान रही है। वास्तव में वैश्विकरण विश्व के लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक अथवा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास की वकालत करने वाली एकमात्र वैश्विक युक्ति है। वैश्विकरण एक ओर जहा आर्थिक विकास को प्रभावित करने का काम करता है वही दूसरी और राष्ट्रो का सामाजिक विकास और संस्कृतियाँ भी इससे अछूती नही हैं । भारत में वैश्विकरण की शुरुआत 1991 में LPG सुधारों की घोषणा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा की गयी जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सम्तुल्य करने के प्रयास तेज हुए। वैश्विकरण के प्रभाव का आंकलन निम्न आंकड़ो से लगाया जा सकता है - 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% थी जबकि भारत में वैश्विकरण के आने के पश्चात वर्ष 2002 और 2012 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 से 8 प्रतिशत हो गयी जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वैश्विकरण का भारतीय बाजारों और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। वैश्विकरण के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद पर विदेशी निवेश में वृद्धि होने से भारतीय बाजारों में आवश्यक वस्तुओ का आयात तथा निर्यात बढ़ा है जिसने रोजगार के नवीन साधनों का विकास किया है। वर्ष 1991 में सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश 0.1% था परंतु इसकी सक्रिय भूमिका ने इसकी हिस्सेदारी को लगभग 2% तक पहुंचा दिया है।

थॉमस फ्रायड मेन के अनुसार, "वैश्विकरण वास्तव में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रोद्योगिकीयो का एकीकरण है इसमें विश्व का मध्यम से छोटे रूप में ऐसा संकुचन हो रहा है जिससे हम दुनिया के एक कौने से दूसरे कौने मे इतनी जल्दी और सस्ते में पहुँच जाए जितने में पहले कभी संभव नहीं था। पूर्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओ की भाँति यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतियों, आर्थिक नीतियों तथा सभी देशो के विदेशी संबंधों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।"

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय परिदृश्य में वैश्विकरण द्वारा उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना है । इसके अतिरिक्त उन चुनोतियों को भी समझने का प्रयास किया गया है जो वैश्विक ग्राम (Global Village) की परिकल्पनाओ मे प्रतिरोध का कार्य कर रही है।

वैश्विकरण द्वारा आर्थिक एवम सामाजिक परिवर्तन

1. शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन- वैश्विकरण ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सुगमता तथा सर्व उपलब्धता को बल दिया है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा केवल सरकारी संस्थाओ के इर्द गिर्द ही विद्यमान नहीं रही बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर निजी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयो का क्रांतिकारी निवेश हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में तकनीक के आगमन एवम नवीन अवधारणाओं के विकसित होने से शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने संबंधी आवश्यकताओं को भी बल मिला है।

इसी दिशा में एक अंतराष्ट्रीय संगठन UNICEF भी कार्यरत है। UNICEF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि विश्व मे 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक लड़के एवम लड़कियों को शिक्षा से लाभप्रद किया जाए। इसी तर्ज पर UNICEF भारत सरकार के साथ 17 राज्यों में एक साझा शैक्षिक कार्यक्रम पर काम कर रही है। जिसका मूल उद्देश्य वर्ष 2022 तक ऐसे बच्चों के आंकड़ो में कमी लाना है जो बच्चे शिक्षा से वंचित OOSC (Out of School Children's) है जिनमे अधिकतर अनुसूचित जातियों, जंजातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यको के बच्चे शामिल हैं।

2. राष्ट्रीय आय में परिवर्तन- भारत के संदर्भ में वैश्विकरण का सक्रिय तथा गतिशील प्रारंभ 1991 से होता है। जिसके तहत उद्योग धंधों का तीव्र विकास हुआ एवम विनिवेश ने वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को हासिल किया हालाँकि विभिन्न कारकों (आर्थिक मंदी, युद्ध काल, प्राकृतिक विषमताए आदि) ने इसे समय समय पर प्रभावित भी किया जिसका सीधा सा असर प्रति व्यक्ति आय से होते हुए राष्ट्रीय आय पर भी दिखाई देता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विकरण विगत दो दशकों से निरंतर भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभांवित कर रही है जिसे निम्न आंकड़ो द्वारा समझा जा सकता है।

तालिका 1 - राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी वित्त वर्ष वार

वित्त वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ में)
1993-94	6,85.912
2007-08	27,60.325
2011-12	73,23.878

3. कृषि क्षेत्र में परिवर्तन- भारतीय कृषि भारत की जनसंख्या के लगभग 60% आबादी को आश्रय तथा रोजगार प्रदान करती है। परंतु वैश्विकरण ने भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धा के दौर में ला दिया है। वैश्विकरण सस्ते तथा गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों को स्थान देता है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषकों के पास आधुनिक कृषि तकनीकों तथा आधुनिक कृषि के तौर तरीको का अभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकतर कृषक वर्ग का निरक्षर रह जाना भी वैश्विकरण के कयासो को बौना साबित कर रहा है। हालांकि भारतीय कृषि ने वैश्विकरण से कई तकनीकों को हासिल भी किया है जिसके अंतर्गत बीज संवर्धन और फव्वारा सिंचाई विधि का भारतीय किसान बड़े पैमाने पर प्रयोग कर लाभांवित हो रहे हैं। वैश्विकरण के कई पहलू ऐसे हैं जो बाजारों की मांग के अनुसार किसानों को उपज पैदा करने हेतु विवश करते हैं। चूंकि भारतीय संस्कृति में कृषक तथा भूमि के संबंध को माता एव पुत्र के समान समझा जाता रहा है। किसान स्वयं तय करता है उसे कृषि भूमि पर क्या उगाना है और कब उगाना है परंतु वैश्विकरण के भारतीय बाजारों पर हावी हो जाने के कारण कृषकों को बाजारों की मांग के अनुरूप कृषि श्रम करना पड़ता है अथवा भूमि अधिग्रहण जैसी विष्मताएँ उत्पन्न होने से कृषको का कृषि क्षेत्र से पलायन बढ़ रहा है।

वैश्विकरण की चुनोतियाँ

1. **प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था-** वैश्विकरण ने बाजारों के स्वरूप को परिवर्तित कर ग्राहकों की माँगो के अनुरूप बनाने का काम किया है। वैश्विक बाजारों में सबसे सस्ती तथा गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओ का दबदबा है। ऐसी बाजार व्यवस्था में चीन अमेरिका और जापान जैसे राष्ट्रो का सामना कर पाना विकासशील राष्ट्रो हेतु एक चुनौती की तरह उभर रहा है। भारतीय बाजार विश्व में सर्वाधिक वृहद बाजार व्यवस्था है अत यहाँ बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओ के आगमन ने local क्षेत्रीय वस्तुओ के लिए भी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की है।
2. **संसाधनों का अभाव-** भारतीय अर्थव्यवस्था का विकसित राष्ट्रो की तुलना में संभावित लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण संबंधित क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव एक गम्भीर चुनोती है।
3. **मानव अधिकारों को खतरा-** कई वैश्विकरण आंदोलनों ने समय समय पर मानव अधिकारों के पक्ष में अपनी आवाज को मुखर किया है। इनके अनुसार वैश्विकरण दोहरे चरित्र वाली व्यवस्था है जिसका एक चेहरा विश्व की सामाजिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाता है तो वहीं दूसरा चेहरा मानव अधिकारों का क्षरण करता है।
4. **लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का विलुप्तिकरण-** वैश्विकरण का लक्ष्य लघु और सूक्ष्म उद्योगों को जीवंत करना था परंतु आधुनिकता के इस दौर में आवश्यक वस्तुओ के क्रय- विक्रय
5. **साइबर क्राइम तथा हेकिंग-** एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत साइबर क्राइम जैसी घटनाओ में हो रही बढ़ोतरी ने वैश्विकरण को कटघरे में ला दिया है। कोई भी विकासशील देश साइबर खतरों की जद से दूर नहीं है। लगातार बढ़ रही हेकिंग की घटनाओ ने वित्तीय जोखिम को भी बढ़ा दिया है। महिलाओ, बलिकाओ तथा छोटे बच्चों के विरुद्ध साइबर क्राइम की घटनाओ ने वैश्विकरण के नकारात्मक स्वरूप से विश्व को परिचित कराने का काम किया है।

निष्कर्ष

उक्त अध्ययन का विश्लेषण करने के पश्चात यह कहा जा सकता है वैश्विकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिल जुला रहा है। एक ओर जहाँ नई आर्थिक नीति के आने से भारतीय बाजारों में आवश्यक वस्तुओ की मांग बढ़ी है तो वही विश्व व्यापार से संबंधित मानदंडों का अनुसरण करता हुआ भारतीय कृषि जगत वैश्विकरण के दुष्परिणामों से जूझ रहा है। वैश्विकरण ने इसके अतिरिक्त कई चुनोतियों को जन्म दिया है जिससे सामाजिक संस्थागत ढांचे को सर्वाधिक ह्रास हुआ है। मानव अधिकारों तथा वित्तीय जोखिम जैसे ज्वलंत मुद्दों ने वैश्विकरण के लक्ष्यों में प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम किया है। भारतीय बाजार व्यवस्था को विश्व बाजार से संबद्ध करने हेतु भारत सरकार के अलावा कई वैश्विक संस्थाएँ भी कार्य कर रही है। ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतिपूर्ण वातावरण में भी स्थिर रखा जा सके।

संदर्भ

1. भारत 2013, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पृष्ट 98
2. शेखर मेदमवार, तपन चौरे, कृषि विपणन योग्य आधिक्य, कल्पाज़ प्रकाशन, 2011
3. डॉ दीपश्री भारत का आर्थिक विकास,न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्रा. लि. 2016
4. Indiabudget.nic.in